सुनवाई तिथि-27-06-2025 की नोटिस

Mahesh Pratap Singh <yogimpsingh@gmail.com> 18 July 2025 at 11:06
To: SWATANTRA PRAKASH <hearingcourts6.upic@up.gov.in>, so nagarvikash8 <so.nagarvikash8@gmail.com>
Cc: nagarvikassection6@gmail.com

In continuation of the guidelines given in the writ petition (civil) 360/2021 filed in the Honourable Supreme Court and the order of Uttar Pradesh Government to do paperless work in the departments, please respond to this email representation. Please curb extra burden on the public exchequer by promoting paperless work.
UTTAR PRADESH INFORMATION COMMISSION
Second Appeal under section 19(3) of the Right to Information Act, 2005
Appeal Registration Number - A-20240700485
File Number - S06/A/1200/2024
Date of hearing: 12/09/2025
Court of hearing: S-6
Applied Date : 07/07/2024 11:02:45 AM
Yogi M P Singh Versus Public information officer SUSHEEL CHANDRA GUPTA,पता : जनसूचना अधिकारी कार्यालय-नगर विकास विभाग अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
Subject- Repeated notices of the Uttar Pradesh state information Commission are being overlooked by the public information officers.
Short submissions of the appellant are as follows.
Reply of the PIO:- The work of filling the annual movable and immovable property statement by the officers of Uttar Pradesh Civil Services through online medium on Sparrow Portal is not worked and monitored at the directorate level. Hence, the desired information is not held at the Directorate level.
1-Submission- The government order was sent by Dhananjay Shukla, Special Secretary of the Government of Uttar Pradesh on 4th January 2024. This mandate is addressed to the Chairman Revenue Council Uttar Pradesh Lucknow, all Additional Chief Secretary, Principal Secretary, Secretary, Government of Uttar Pradesh, all the heads of departments and chief office heads, Uttar Pradesh all the divisional commissioners of Uttar Pradesh, the District Magistrate of Uttar Pradesh.
2- Submission- Director at the directorate local body Lucknow had to direct subordinates specially provincial civil servants to submit Entire movable and immovable property details on the Sparrow Portal of the government of Uttar Pradesh by using their ID and passwords.
3- Submission- This implies that the Director at the directorate local body Lucknow did not ensure the compliance of the government order sent through the special secretary of the government of Uttar Pradesh Mr Dhananjay Shukla on 4th January 2024.
4- Submission- Here one thing must be noted that the information seeker is not seeking information concerning the declaration of assets but the appellant is seeking information regarding the compliance of the government order and communications exchanged regarding it by the accountable officer of the government.
5- Submission- It is most unfortunate that the public information officer denied

the information on the ground that The work of filling the annual movable and immovable property statement by the officers of Uttar Pradesh Civil Services through online medium on Sparrow Portal is not worked and monitored at the directorate level. Hence, the desired information is not held at the Directorate level..
6- Submission- This implies that the director of the Directorate local body Lucknow did not make compliance of the government order by directing the subordinates to submit their both movable and immovable properties on the Sparrow Portal by using their ID and password. This is not the mistake of the fact but it is a mistake of the law and tantamount to indiscipline in performing the public duty. It is not expected from such a senior rank officer who has retained such a highest level of responsibilities.
7-Submission-Think about the ancient monarchies when the people were awarded capital punishment for violating the orders of the Kings but at present such government orders are put into the dustbin.
Whether it is not a failure of the democracy in the country and is not reflecting the anarchy in the working of the government machinery because of such an arrogant working style.
What is the need to amass huge wealth disproportionate to known sources of income because such a step is causing one to escape from following the government order?
8-Submission-If no information is made available by the director local body, then this implies that he has not taken any action on the order of government as follows.
2. अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ
तैनात उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के समस्त अधिकारियों को
31 दिसम्बर, 2023 तक धारित समस्त चल-अचल सम्पत्ति का विवरण
sparrow-pcs.up.gov.in पर अपने आई 0 डी0 पास-वर्ड का प्रयोग करते हुए
अनिवार्य रूप से 31 जनवरी 2024 तक ऑन-लाइन भरने हेतु अपने स्तर से
निर्देशित करने का कष्ट करें। This implies that the appellant is seeking information concerning the compliance of this government order.
Date- 18/07/2025 O God help me
Yogi M P Singh, Mobile number- 7379105911

[Quoted text hidden]

---

replnagarvikaas.pdf
312K

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-6
संख्या-30सू0अ0/नौ-6-2025
लखनऊ: दिनांक: 26 जून, 2025

जन सूचना अधिकारी,
स्थानीय निकाय निदेशालय
लखनऊ।

कृपया पीठासीन अधिकारी, सु0एस-6,उ0प्र0सूचना आयोग,लखनऊ की नोटिस संख्या-202506S06 N200476,दिनांक 25.06.2025 अपील संख्या- S06/A/1200/2024, पंजीकृत संख्या-A-20240700485 (छायाप्रति-संलग्न)का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा योगी एमपी सिंह, सुरेकापुरम कॉलोनी जबलपुर रोड मिर्जापुर सिटी जनपद- मिर्जापुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत द्वितीय अपील दिनांक-07.07.2024 के संबंध में दिनांक 27-06-2025 को सुनवाई निर्धारित की गई है।

2- उपर्युक्त अपील में दिनांक 07.07.2024 की सुनवाई में मा0आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए उक्त आदेश के क्रम में वांछित कार्यवाही पूर्ण करते हुए आगामी सुनवाई दिनांक 27.06.2005 हेतु निर्धारित तिथि से दो दिन पूर्व अपना लिखित कथन (ईमेल hearingcourtts6.upic@up.gov.in) अथवा विभागीय पोर्टल पर (https//upsic.gov.in/) पर स्कैन करते हुए पी0डी0एफ0के फॉरमेट में मा0राज्य सूचना आयोग आयुक्त, सुनवाई कक्ष संख्या एस-6 के समक्ष कृत कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उ0प्र0सूचना की नोटिस दिनांक-25.06.2025 के संबंध में आगामी सुनवाई दिनांक 27.06.2005 में अपना लिखित कथन **(ईमेल** hearingcourtts6. upic@up.gov.in) अथवा विभागीय पोर्टल पर (https//upsic.gov.in/) पर स्कैन करते हुए पी0डी0एफ0के फॉरमेट में मा0राज्य सूचना आयोग आयुक्त, सुनवाई कक्ष संख्या एस-6 के समक्ष कृत कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत करने के हेतु उक्त सुनवाई में निर्धारित तिथि एवं समय में उपस्थिति होने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(गौरव दुबे)
अनुभाग अधिकारी /
जन सूचना अधिकारी

संख्या एवं दिनांक- तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 पीठासीन अधिकारी, सु0एस-6,उ0प्र0सूचना आयोग,लखनऊ को उनकी उपर्युक्त नोटिस संख्या-202506S06N200476,दिनांक 25.06.2025 दिनांक 25.06.2025 के क्रम में।
2 योगी एमपी सिंह, सुरेकापुरम कॉलोनी जबलपुर रोड मिर्जापुर सिटी जनपद- मिर्जापुर-231001

आज्ञा से,

(गौरव दुबे)
अनुभाग अधिकारी /
जन सूचना अधिकारी

राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश।

समक्षः मा0 राज्य सूचना आयुक्त, श्री स्वतंत्र प्रकाश गुप्तः।

अपील संख्या S11/A/1200/2024

श्री योगी एमपी सिंह..अपीलार्थी

बनाम

विपक्षी/जनसूचना अधिकारी, कार्यालय–निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, जनपद लखनऊ...........प्रतिवादी।

आदेश

अपीलीय प्रकरण प्रस्तुत हुआ। पुकार करायी गयी। पुकार कराये जाने पर उभय पक्ष अनुपस्थित है।

विपक्षी/जनसूचना अधिकारी कार्यालय–नगर विकास अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन लखनऊ को अपीलार्थी का सूचना आवेदन धारा 6(1) की प्रति एवं आयोग के आदेश दिनांक 20.11.2024 की प्रति संलग्न कर पुनः नोटिस प्रेषित की जाये। अपील वास्ते अगली सुनवाई दिनांक 27.06.2025 को पेश हो।

(स्वतंत्र प्रकाश गुप्तः)
राज्य सूचना आयुक्त
01.05.2025

राकेश चन्द्र जोशी

राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश।

समक्ष : मा0 राज्य सूचना आयुक्त, श्री स्वतंत्र प्रकाश गुप्तः।

(पंजीकरण संख्या–ए–20240700485)

अपील संख्या एस–06/ए/1200/2024

श्री योगी एमपी सिंह.....अपीलकर्ता।

बनाम

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ ..... प्रतिवादी।

आदेश

अपीलीय प्रकरण प्रस्तुत हुआ। पुकार करायी गयी। पुकार पर उभय पक्ष अनुपस्थित है। उभय पक्षों की अनुपस्थिति में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

न्यायहित में उभय पक्षों को अवसर प्रदान किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि वह अग्रिम तिथि पर आयोग के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही अग्रसरित की जायेगी।

आज पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए विपक्षी/जनसूचना अधिकारी को नोटिस प्रेषित की जाये।

वाद वास्ते अगली सुनवाई दिनांक 28.01.2025 को पेश हो।

(स्वतंत्र प्रकाश गुप्तः)
राज्य सूचना आयुक्त
20.11.2024

धनंजय यादव